दिनांक 20 दिसम्बर, 1985 -

सं श्रो वि ्हिसार/45-85/51592. — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मैनेजिंग डायरैक्टर, हरियाणा स्टेंट माईनर इरीगेशन, ट्यूबबैल कारपोरेशन, लिं∘, चन्डीगढ़, (2) श्रीधशासी श्रीभयन्ता, सिरता मन्टीनैंस डिविजन, माईनर इरीगेशन, ट्यूबबैल कारपोरेशन लिं∘, सिरसा, के श्रीमक श्री सरनाम सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

भीरु चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रव, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) हारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके हारा सहकारी ग्रधिसूचना सं० 9641-1-अम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी ग्रधिनियम की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादगस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :---

क्याश्री सरनाम सिंह, पुत्र श्री तोता राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह - किस राहत का हकदार है ?

सं. घो.वि./हिसार/67-85/51599--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि , सहायक निदेशक, भेड़व ऊन विकास, हरियाणा, भिवानी के श्रमिक श्री नात्थु राप्नु तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्री द्योगिक विवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायणिय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय सभझते हैं ;

इसलिए, ग्रव, श्रीशोगिक विवाद शिविनियम, 1947, की शारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिवितयों का प्रयोग करते हुये, हरियाण। के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रीधसूचना सं. 9641-1-श्रम, 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी श्रीधसूचना की शारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसुंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पैचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उनत प्रवन्धकों तथा श्रिमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला या उनत विवाद हो सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री नात्यु राम की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस, राहत का ह्कदार है ?

दिनाँक 27 दिसम्बर, 1985

सं. मो.वि./भिवानी/72-85/52427.—-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) दी सैन्ट्री, एच०एस०ई०बी०, चण्डीगढ़, (2) सुत्ररितर्टेंडिंग इन्जीनियर, एच०एस०ई०बी०, भिवानी (8) सुपरितर्टेंडिंग इन्जीनियर, स्रो० डिवियन, एच०एस०ई०बी०, चरखी दादरी के श्रमिक श्री प्रताप सिंह तथा उसके प्रवन्त्रकों के बीच इसमें इनके बाद लिख्लित गामले में कोई स्रोद्योगिक विदाद है;

घोर चूंकि हरियाणा के राज्यपात विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बालनीय समझते हैं ;

- इसलिये, अब, मीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपदारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 'सं० 9641-1-अन-78/32573, दिनांक 6 नाम्बर 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक, की विवाद प्रस्तु या उसमे सुसंगत या उससे सम्युन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जं। कि उक्ते प्रबन्धकों तथा अभिक के भीच या तो विवाद प्रस्तु मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री तोख राज की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?